

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न सं. 417\*

जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 5 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है

**बीएचईएल को लाभप्रद बनाया जाना**

**417\*. डा. वी. मैत्रेयन:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने अगले दो वर्षों के दौरान घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को पुनरुज्जीवित करने हेतु कोई कार्यनीति बनाई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा तिरुचिरापल्ली एवं तिरुमयम में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) संयंत्रों को लाभप्रद बनाने हेतु कौन-से कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या सरकार के पास चेन्नई में बीएचईएल के पाइपिंग केंद्र को तिरुमयम इकाई में स्थानांतरित करने की कोई योजना है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री  
(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

\*\*\*\*\*

‘बीएचईएल को लाभप्रद बनाया जाना’ के संबंध में डा. वी. मैत्रेयन द्वारा पूछे गए दिनांक 05.04.2018 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 417 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 31 उद्यम (सीपीएसई) हैं, जिनमें से 13 सीपीएसई घाटे में चल रहे हैं। भारी उद्योग विभाग समय-समय पर अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सीपीएसई के कार्यों की समीक्षा करता है और पणधारकों के परामर्श से प्रत्येक सीपीएसई (घाटे में चल रहे अथवा अन्यथा) के निष्पादन पर उपयुक्त निर्णय/प्रतिक्रिया निर्धारित की जाती है। घाटे में चल रहे सीपीएसई के लिए अनेक पुनरुद्धार पैकेज (वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता) उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग): भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) की भारत के विभिन्न हिस्सों (तिरुचिरापल्ली और तिरुमयम सहित) में 17 विनिर्माण इकाइयां हैं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान घाटे की सूचना दी, जोकि मुख्य रूप से कमजोर कारोबारी माहौल के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रचालन और लाभ के स्तर में कमी आई। तथापि, 2016-17 में, भेल ने ₹628 करोड़ के पीबीटी (कर-पूर्व लाभ) के लाभ के साथ वापसी की। इसके लिए तिरुचिरापल्ली और तिरुमयम सहित अधिकतर विनिर्माण इकाइयों ने सकारात्मक योगदान दिया। लागत अनुकूलन, तीव्र निष्पादन, निष्पादन-योग्य आर्डरों में वृद्धि आदि सहित कई ऐसे कदम थे, जिनकी सहायता से 2016-17 में भेल की लाभप्रदता में सुधार आया।

(घ) और (ड): इस समय भेल में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*